

कृषि विभाग

दिनांक 1 अगस्त, 2006

संख्या 1791-कृषि-II (3)-2006/13926.—पंजाब गन्ना (क्रय तथा आपूर्ति विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2004, की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, दिनांक 16 नवम्बर, 2004 को ऐसी तिथि के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम लागू हुआ समझा जाएगा।

आशा शर्मा,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

कृषि विभाग।

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 1st August, 2006

No. 1791-Agri.-II (3)-2006/13926.—In exercise of powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Act, 2004, the Governor of Haryana hereby appoints the 16th November, 2004 to be the date on which the said Act shall be deemed to have come into force.

ASHA SHARMA,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Agriculture Department.

कृषि विभाग

दिनांक 1 अगस्त, 2006

संख्या 1791-कृषि-II (3)/2006/13929.—पंजाब गन्ना (क्रय तथा आपूर्ति विनियमन) अधिनियम, 1953 (1953 का पंजाब अधिनियम 40) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, 2005-2006 के मौसम के दौरान चीनी कारखानों को गन्ना आपूर्तिकारों द्वारा उनके, समनुदेशित क्षेत्रों में आपूर्ति किए जा रहे गन्ने की चीनी कारखानों द्वारा भुगतान की जाने वाली गन्ने की अगेती, मध्यम तथा पछेती किस्मों की कीमत क्रमशः 135/-, 123/- तथा 121/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से विनियमित करते हैं।

आशा शर्मा,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

कृषि विभाग।

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 1st August, 2006

No. 1791-Agri.-II (3)-2006/13929.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of the Sub-section (1) of Section 14 of the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Act, 1953 (Punjab Act 40 of 1953), the Governor of Haryana hereby regulates the price of sugarcane being supplied to the sugar mills during the season 2005—2006 to be paid by the sugar mills to the cane suppliers in their assigned areas at the rate of Rs. 135/-, 123/- and 121/- per quintal for early, mid and late varieties of cane respectively.

ASHA SHARMA,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Agriculture Department.

[To be substituted bearing same number & date]

WELFARE OF SCHEDULED CASTE AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT

The 30th March, 2006

No.769-SW (2)-2006.—The Governor of Haryana is pleased to re-constitute a District Consultative Committee in place of District Harijan Sahakar Samiti (Standing Committee) and District Level Committee for monitoring the progress of cases under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Protection of Civil Right Act, 1955 as under :—

The District Consultative Committee

- | | |
|--|------------------|
| 1. Deputy Commissioner | Chairman |
| 2. Additional Deputy Commissioner | Vice-Chairman |
| 3. Superintendent of Police of the District concerned | Member |
| 4. All SC/BC Members of the Haryana Vidhan Sabha of the District concerned | Member |
| 5. Four non-official SC Members to be nominated by the Deputy Commissioner | Member |
| 6. S. D. O. (C) of the concerned District | Member |
| 7. District Attorney of the concerned District | Member |
| 8. District Welfare Officer of concerned District | Member Secretary |

Functions of the Committee

To review the progress of cases registered and compensation paid under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Protection of Civil Right Act, 1955.

2. To review the implementation of Housing Scheme for Scheduled Castes and Vimukat Jatis.

3. To review the implementation of any other Scheme of the Department of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes.

Other

1. The Headquarter of the Committee will be the concerned District Headquarter.

2. The Committee will meet at discretion of the Chairman at least once in every quarter of the year.

3. No TA/DA will be given to the non-official members (excluding MLAs).

DALIP SINGH,

Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2006

क्रमांक 1831-ज-2-2006/13748.—श्री नोबत राम पुत्र स्व० श्री श्योकरण, निवासी गांव नांगल काठा, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1984-ज-1-78/1216, दिनांक 10 जनवरी, 1979 द्वारा 150/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी। इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434-ज-2-2002/9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5000/- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था।

2. अब श्री नोबत राम की दिनांक 20 नवम्बर, 2003 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व० श्री नोबत राम की पत्नी श्रीमती श्रवण देवी के नाम फसल खरीफ 2004 से 5000/- रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

आर० बी० खरवन्दा,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,

राजस्व विभाग।

चण्डीगढ़ :

दिनांक 19 जुलाई, 2006